**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2265**

**सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)**

**रोजगार के नए अवसर**

**2265. श्री गणेश सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(क)** रोजगार के नए अवसरों के बारे में सरकार के पास उपलब्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सरकारी विभागों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से अस्थायी नियुक्ति के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष कितने लोगों को रोजगार मिला है;

(घ) क्या सरकार के पास निजी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों की संख्या का ब्यौरा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है और यह बहु हितधारक पहल है और तदनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से रोजगार खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों आदि पर जानकारी आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। एनसीएस निजी और सरकारी क्षेत्रों से नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों, कौशल / प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि पर जानकारी सहित सभी करियर संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 15.11.2024 तक, एनसीएस पोर्टल पर 3.52 करोड़ से अधिक (जिसमें अन्य के साथ-साथ निजी क्षेत्र शामिल है) रिक्तियां जुटाई गई हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रीय रोजगार मेले का शुभारंभ किया था। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 45-50 शहरों में केन्द्रीय स्तर पर अब तक कुल **13** रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं। रोजगार मेले के भाग के रूप में, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठनों में रिक्त पदों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मिशन मोड में भरा जा रहा है।

इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/रेलवे में पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने का निर्देश दिया गया है।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाला लोक उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में नियमित कर्मचारियों, अनियमित/ दैनिक दर कामगार तथा संविदा कामगार/कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या प्रदान करता है। नवीनतम लोक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, सीपीएसई क्षेत्रों में 2022-23 में 14.90 लाख लोगों को नियोजित किया गया। विस्तृत सूचना **https://dpe.gov.in/publication/pe-survey/pe-survey-report** पर उपलब्ध है।

*****